घरेलू बाजार में नहीं बढ़ेंगे चीनी के दाम

नई दिल्ली स्थित एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को खाद्य व सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) केवी थॉमस ने उद्यमियों को राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार वितरित किए। जागरण

राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार

राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार-2011 समारोह में श्रेष्ठ सेवा मानक लिए सर्वोत्तम पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के डीएवी एसीसी वरिष्ठ माध्यमिक पब्लिक स्कूल को दिया गया। श्रेष्ठ गुणवत्ता मानक पुरस्कार नोकिया सीमेंस नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कांचीपुरम (तमिलनाडु) को प्रदान किया गया। सेवा उद्योग वर्ग का पुरस्कार आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड, नोएडा (उप्र.) को मिला। लघु स्तरीय निर्माण उद्योग वर्ग में टेक्नोक्रेट कनेक्टिविटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, रुद्र प्रयाग (उत्तराखंड) ने पुरस्कार जीता है।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आगामी तीन सालों तक देश में चीनी का पर्याप्त उत्पादन होगा, जो घरेलू जरूरतों के मुकाबले अधिक होगा। खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने कहा कि चालू साल में 2.4 करोड़ टन से अधिक उत्पादन का अनुमान है। वहीं, घरेलू खपत 2.2 करोड़ टन रहने की संभावना है।

चीनी उद्योग को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के बाद घरेलू बाजार में चीनी के मूल्य में तेजी की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन थॉमस ने इन कयासों को सिरे से खारिज किया है। वैसे, चालू चीनी वर्ष (सितंबर, 2012 से अक्टूबर, 2013) में पिछले साल के 2.6 करोड़ टन के मुकाबले उत्पादन कम हुआ है।

खाद्य मंत्री शुक्रवार को यहां राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार-2011 समारोह में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। समारोह में श्रेष्ठ सेवा, श्रेष्ठ गुणवत्ता, सेवा उद्योग वर्ग और लघु स्तरीय निर्माण उद्योग वर्ग में उम्दा प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया गया। चीनी उद्योग को पटरी पर लाने और उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव पर काबू पाने के लिए हाल ही में कृषि मंत्री शरद पवार के साथ विस्तृत चर्चा की गई। इसी के आधार पर घरेलू जरूरतों से अधिक उत्पादन का आकलन किया गया है। बैठक में ही एक परिपत्र तैयार किया गया, जिस पर कानपुर के शुगर इंस्टीट्यूट में गंभीर विचार-विमर्श किया जाएगा।

यह बैठक मई माह के तीसरे सप्ताह में होगी, जिसमें चीनी उत्पादन से जुड़े सभी पक्षकार शामिल होंगे। इसी महीने के शुरू में सरकार ने चीनी उद्योग को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया।

इसके बाद से घरेलू बाजार के बेकाबू होने की आशंका बढ़ने लगी है। राशन प्रणाली के लिए सब्सिडी वाली चीनी अब राज्यों को खरीदनी होगी, केंद्र सरकार उन्हें सब्सिडी का भुगतान करेगी।

दैनिक जागरण

27/5/13